प्रेषक.

(12)

सुरेन्द्र सिंह रावत अपर सचिव उत्तराखण्ड शासनं।

सेवा में.

प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 21 अप्रैल 2011

विषय--

जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत देहरादून सीवरेज योजना के निर्मित होने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के पाँच वर्षों के आपरेशन एवं मैनटीनेन्स कार्यों हेतु प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 290 / न0यो० अनु०—जे०एन०एन०यू०आर० एम० / 26 दिनांक 24.02.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत देहरादून सीवरेज योजना के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के पाँच वर्षों के आपरेशन एवं मैन्टीनेन्स हेतु उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन अनुसार लागत ₹ 12.77 करोड़ (बाहर करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

- 1— इसके द्वारा किसी भी धनराशि के व्यय की स्वीकृति न देकर मात्र प्रशासकीय स्वीकृति दी जा रही है। उक्त स्वीकृत अनुमानित लागत के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी आधार पर न्यूनतम दर एवं ठेकेदार/सेवा प्रदाता फर्म का चयन किया जायेगा। जेoएनoएनoयूoआरoएमo कार्यक्रम के अन्तर्गत देहरादून सीवरेज योजना के कार्य पूर्ण होने के पश्चात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के आपरेशन एवं मेन्टीनेंस की आवश्यकता पर उक्त स्वीकृत अनुमानित धनराशि की सीमान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए व्यय की स्वीकृति शासन से प्राप्त की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त विद्युत/डीजल की खपत के सापेक्ष व्यय हेतु धनावंटन यथासमय यथाआवश्यकता कर लिया जाय।
- 2— कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- 3— कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 4— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।
- 5— एक मुश्त प्राविधानों का कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
- 6— कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता से कार्य स्थल का भलीमॉित अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- 7— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- 8— स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।
- 9— योजना की स्वीकृत लागत में सेन्टेज हेतु पृथक से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।



10— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ—साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11— मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV—219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करें।

12— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 13/XXVII (2)/2011 दिनांक 20 अप्रैल 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

> भवदीय (सुरेन्द्रं सिंह रावत) अपर सचिव

संख्या 305 ()/ उन्तीस(2) / 11-2(117प0) / 2010,तददिनांकृ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 पेयजल मंजी जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2- स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

3-- निजी सचिव-सचिव पेयजल को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल!

5- जिलाधिकारी, देहरादून।

6— निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।

र्न निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

9- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।

10-अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सम्बन्धित जनपद।

11-वित्त अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।

12-गार्ड फाईल।

DOF

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी) ( उप सचिव